



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2003/माघ 1, 1924

No. 27]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2003/MAGHA 1, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2003

अंतिम निष्कर्ष

विषय :—इंडोनेशिया और थाईलैण्ड से साइट्रिक एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/11/2002-डी.जी.ए.डी.—भारत सरकार 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:-

क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के तहत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 सिटुरजिया बायो कैमिकल्स लि0 की ओर से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें इंडोनेशिया और थाईलैण्ड (जिन्हें इसके बाद संबद्ध

देश कहा गया है) के मूल के साइट्रिक एसिड (जिसमें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

- ii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये पाटन के आवेदन की प्राप्ति के विषय में संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोग को सूचित किया ।
- iii) प्राधिकारी ने दिनांक 16 अप्रैल 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत सीमाशुल्क उपशीर्ष 2918.14 के तहत आने वाले संबद्ध देशों से साइट्रिक एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी कार्रवाई आरंभ की गई ।
- iv) प्राधिकारी ने दिनांक 14-6-2002 को प्रारंभिक निष्कर्षों पर एक प्रति अधिसूचित की और निम्नलिखित हितबद्ध पक्षों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी और उन्हें इस पत्र के जारी होने के चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचारों से, यदि कोई हो, अबगत कराने का अनुरोध किया गया ।

आयातक/उपयोग कर्ता

1. मै0 अमीजल कैमिकल्स, मुम्बई
2. मै0 जैन प्रोसेस फूड लिमि0, जलगांव
3. मै0 पोजी फार्माकैमिकल प्राइवेट लिमि0, अहमदाबाद
4. मै0 सी0जे0 शाह एंड कं0, मुम्बई
5. मै0 सिपला लिमि0, पूणे
6. मै0 जैन प्रोसेस फूड लिमि0, जलगांव
7. मै0 सुनील कैमिकल्स, विरार, जिला थाने

8. मै0 क्लेरेन्ट (इंडिया) लिमि0, थाने
9. मै0 पार्ले इन्टरनेशनल लिमि0, मुम्बई

निर्यातक

1. मै0 पं0 बुडी एसिड जया टी0बी0के0, इंडोनेशिया
2. मै0 थाई साइट्रिक एसिड कं0 लि0, थाईलैंड
3. मै0 एशिया साइट्रिक कं0 लिमि0 थाईलैंड
4. मै0 साइट्रिक एसिड इन्डस्ट्री लिमि0, थाईलैंड

घरेलू उद्योग

मै0 सिटुरजिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड

- v) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली में संबंध देश के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे संबंध देश के निर्यातकों और हितबद्ध पक्षों को इस पत्र के जारी होने के चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दें ।
- vi) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को दिनांक 21-10-2002 को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । इन पक्षों से प्रतिपक्षी पक्षों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रतियां लेने और उनका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, देने की सलाह दी गई थी ।
- vii) निम्नलिखित हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राथमिक निष्कर्षों/सार्वजनिक सुनवाई के प्रतिउत्तर में निवेदन प्रस्तुत किये गये थे ।

क. मैसर्स सिटुरजिया बायोकेमिकल्स लिमि0

ख. मै0 क्लेरेन्ट (इंडिया) लिमि0

ग. मै0 बिल्ट बायोकेमिकल्स लिमि0

घ. निर्यातकों की ओर से इंडोनेशिया सरकार के विचार

ड. निर्यातकों की ओर से थाइलैंड सरकार के विचार

viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

ix) जांचावधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरे का प्रबंध करने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड से अनुरोध किया गया था

x) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा किये जाने से पूर्व हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये गये तर्कों जिन्हें अधिसूचित किये गये प्रारंभिक निष्कर्षों में दिया गया है, को संक्षिप्तता की खातिर यहां दोहराया नहीं गया है । तथापि, हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये गये तर्कों पर प्रकटीकरण और अथवा इन निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है ।

xi) उपर्युक्त नियम के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिये आवश्यक तथ्यों/आधार को दिनांक 11-12-2002 को ज्ञात हितबद्ध पक्षों के लिये प्रकट किया गया था ।

xii) सामान्यतया स्वीकार्य लेखाविधि के सिद्धान्तों और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत निकालने और भारत में संबद्ध वस्तु को तैयार करने और उसकी बिक्री करने की लागत के बारे में लागत जांच की गई थी ।

निम्नलिखित घरेलू उत्पादों के लागत के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे व उन्हें विश्लेषित किया गया था:-

1. मैसर्स सिटुरजिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड

- xiii) प्राधिकारी ने यथोचित सीमा तक याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना की जांच की ।
- xiv) इस अधिसूचना में चिन्ह **** से हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के तहत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है ।
- xv) यह जांच 1 अप्रैल 2001 से 31 दिसम्बर 2001 तक अर्थात् जांचावधि के लिये, की गई थी ।

ख. निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

2.1 घरेलू उद्योग के विचार

- क. याचिकाकर्ता द्वारा संबंध देशों से पाटन का मार्जिन भी 2 प्रतिशत से अधिक की सीमा जिसे निर्यात मूल्य के प्रतिशत में व्यक्त किया गया है, में होना साक्षित किया गया है । यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि संबंध देशों से आयातों की मात्रा न्यूनतम है और निकाली गई लागत पद्धति के आधार पर पाटन का मार्जिन इंडोनेशिया और थाइलैंड के लिये क्रमशः 70.95 प्रतिशत और 55.08 प्रतिशत है ।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा दायर मौजूदा याचिका को निर्यातकों द्वारा अंधाधुन्य पाटन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही गंभीर स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए । घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को संबंध देशों से निर्यातकों द्वारा अपनाये गये गम्भीर पाटन के आलोक में भी देखा जाना चाहिए ।

यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों के प्रत्येक आयात की मात्रा, न्यूनतम की सीमा से अधिक है। आयातों के प्रभाव का सकल आकलन, समुचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात मूल्य, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित मूल्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से सकल रूप से होने वाली क्षति का आकलन करने का अनुरोध किया है।

आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा पिछले कई वर्षों से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी, अन्य, खिलाड़ियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। भारत में बाजार की मौजूदा स्थिति के लिये एक मात्र कारण संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा पाटे गये मूल्य हैं।

ग. निर्धारित फॉर्मेट में किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। जिससे पाटन मार्जिन तैयार करने के लिये माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता हो सके। अतः यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से निर्यातक इस तथ्य से अवगत हैं कि वे पाटित् मूल्यों पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं।

घ. प्रारंभिक निष्कर्षों के उपरान्त आयातकों अथवा निर्यातकों से किसी से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यह माना जाता है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं देनी है। इन परिस्थितियों के तहत, हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करेंगे कि वे कृपया, शीघ्र ही प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करें।

ड. मैसर्स सिंदुरगुरिया की 6000 मीटरीटन प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के अलावा मैसर्स बिल्ट बायोकेमिकल्स लिमि0 की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 25000 मीटरी टन है। साइट्रिक एसिड के लिये घरेलू मांग लगभग 11000-12000 मीटरी टन प्रतिवर्ष है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग से काफी अधिक है, और यदि साइट्रिक

एसिड को देश में पाटे जाने के लिये अनुमत किया जाता है तो घरेलू उद्योग को इतनी अपूर्णीय क्षति होगी, जिससे कि इसे प्रचालित करना मुश्किल हो जायेगा।

2.2 आयातकों के विचार

मैसर्स क्लेरियान्ट (इंडिया) लिमिटेड

- क) शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका में उल्लेख किया गया है कि मैसर्स भारत स्टार्च को वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में बंद किया गया था और उनके साइट्रिक एसिड सयंत्र को दिसंबर 2001 के तीरे सप्ताह में ही फिर से शुरू किया गया। यह आश्चर्यजनक है कि एक तरफ पाटन होने का आरोप है और दूसरी तरफ, प्रवर्तन अधिसूचना उल्लेख करती है कि मैसर्स भारत स्टार्च, जो कि साइट्रिक एसिड के अन्य उत्पादक है जांचाधीन अवधि के दौरान बंद थी। घरेलू उद्योग का पाटन का यह आरोप अपुष्टिकर है।
- ख) पर्याप्त और ठोस ब्यौरे जैसे कि उत्पादन की लागत, आदि उपलब्ध न कराये जाने की बात एक अड़चन पैदा करने वाली बात होगी क्योंकि आयातकों के रूप में हम यह जाने वगैर कि पाटन का आरोप सही है अथवा नहीं, अपने आशय को पूरा अथवा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे।
- ग) बिना किसी पूर्वाग्रह के, पाटन मर्जिन और क्षति आकलन के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं और उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि एक तरफ आयातों की मीटरी टन में मात्रा बताई जा रही है और दूसरी तरफ उन्हें प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा रहा है। क्षति आकलन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उर्ध्वगामी प्रवृत्ति को दर्शाती हुई कुल मांग के बावजूद भी घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कमी आई है।

- घ) मैसर्स क्लेरैन्ट (इंडिया) लिमिटेड, टैक्सटाइल कैमिकल्स के विनिर्माण के लिए 12 मीटरी टन/महीना साइट्रिक एसिड का आयात करती है। वे याचिकाकर्ता कम्पनी और मैसर्स भारत स्टार्च दोनों से साइट्रिक एसिड की अधिप्राप्ति करते हैं।
- ड.) आयातकों ने आंशका व्यक्त की है कि यदि अनंतिम शुल्क को पंक्का किया जाता है तो इससे भारत में इन दो विनिर्माताओं की साइट्रिक एसिड के लिए पूर्ण एकाधिकार होने की स्थिति हो जाएगी क्योंकि चीन से होने वाले आयातों पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है।

2.3 इंडोनेशिया सरकार के विचार

- क) इंडोनेशिया सरकार ने प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया के निर्यातक द्वारा अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया के निर्यातक द्वारा कमियों को दूर कर दिये जाने पर पाटन के आरोप की फिर से जांच करें।
- ख) इंडोनेशिया सरकार जानना चाहती है कि क्या 456.7 अमेरिकी डालर का शुल्क, पूरे पाटन मार्जिन पर है अथवा क्षति को दूर करने के स्तर पर, जो बात निष्कर्ष के वृत्तान्त 24 से स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, वे यह बात भी जोर देकर कहते हैं कि यदि शुल्क को पूरे पाटन मार्जिन पर क्षति को दूर करने पर आधारित किया जाता तो साइट्रिक एसिड के लिए गैर-क्षतिकारक मूल्य की गणना, विश्व में उच्चतम होगी।
- ग) उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत में घरेलू विनिर्माता की अक्षमता के स्तर की वजह से उनके उत्पादन की लागत अधिक हो सकती है अथवा याचिकाकर्ता ने शायद सामान्य मूल्य को स्थापित करने के लिए अपनी स्वयं की लागत को भी इसमें शामिल किया है।
- घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते की धारा 3.4 में यह अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित करने में सभी ज्ञात पहलुओं पर विचार किया जाए कि क्या क्षति का कारण पाटित आयात हैं।

- ड.) घरेलू उद्योग अन्य सामान एवं साइट्रिक एसिड का भी उत्पादन करती है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि क्या अन्य क्षेत्रों में कम्पनियों के कार्यनिष्पादन के कारण कथित क्षति हुई है।
- च) इंडोनेशिया सरकार को अपने हित की सुरक्षा करने में मुश्किल हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता को गोपनीयता का उच्च स्तर प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ता के अगोपनीय निवेदन की जांच नहीं हुई है।
- छ) सामान्य मूल्य स्थापित करने में उपयोग में लाई जाने वाली उत्पादन की लागत की सूचना के लिए स्रोत प्रदान न किए जाने के लिए कोई औचित्य नहीं है और इसलिए विश्व व्यापार संगठन के समझौते की धारा 6.5.2 के आलोक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उपयोग में लाई गई सूचना के स्रोत और प्रस्तुत किए गए संकेतकों के वास्तविक मूल्य को बताएं।
- ज) याचिकाकर्ता, वर्ष 1999-2001 के दौरान पूरी क्षमता पर प्रचालन कर रहे थे। वर्ष 2000-2001 में याचिकाकर्ता ने बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य दोनों में वृद्धि दर्शाई है जबकि जांचाधीन अवधि में बिक्री की मात्रा में कमी हुई है लेकिन बिक्री मूल्य अपने स्थान पर बने रहे, इस प्रकार, इकाई बिक्री मूल्य के साथ मूल्यों में मूल्यहास होने का कोई साक्ष्य नहीं है।
- झ) आवेदनकर्ता ने कार्रवाई में अन्य भारतीय उत्पादन को शामिल करने की इच्छा व्यक्त नहीं की क्योंकि इसके लिए कई कारण हो सकते थे जैसे कि अन्य उन भारतीय उत्पादकों से समर्थन की कमी, जिनका भविष्य में साइट्रिक एसिड मार्किट में भरोसा हो।

2.4 इंडोनेशिया सरकार द्वारा व्यक्त विचारों पर प्राधिकारी द्वारा जांच

- क) प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली में पूर्ण उत्तर दायर नहीं किया है। इसका उल्लेख प्रारंभिक निष्कर्षों में पैरा 11 में किया गया है।

- ख) पाटन मार्जिन अथवा क्षति दूर करने के स्तर तक की सीमा तक शुल्क संयोजन के बारे में प्राधिकारी, पाटन मार्जिन के बराबर अथवा कम का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं और जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग होने वाली क्षति दूर होगी ।
- ग) निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के संगत परिशिष्ट में उत्पादन की लागत के बारे में पूर्ण आंकड़े नहीं दिए हैं, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 11(ग) में इंगित किया गया है । अतः प्राधिकारी, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उत्पादन की लागत और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाध्य है ।
- घ) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, सभी घटकों की जांच की गई है ।
- ड.) प्राधिकारी नोट करते हैं कि साइट्रिक एसिड की लागत निकालने और उत्पादन में क्षति से संबंधित घटकों को ही इस जांच में ध्यान रखा गया है ।
- च) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के नियम 6 और नियम 7 के आलोक में दिनांक 16 अप्रैल 2002 की प्रवर्तन की अधिसूचना के साथ-साथ निर्यातकों को याचिकाकर्ता के अगोपनीय निवेदनों को प्रेषित किया गया है ।
- छ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचावधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य दोनों में महत्वपूर्ण कमी आई है । बिक्री मूल्य में आई कमी जबकि सीमांतिक है लेकिन यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जांचावधि के दौरान घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री की मात्रा में काफी कमी हुई है और ऐसा होने का कारण घरेलू उद्योग यह प्रयास है कि वह उसी स्तर का बिक्री मूल्य बनाए रख सके ।
- ज) प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की लागत के बारे में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लेखा और रिकार्ड की पूरी और विस्तृत जांच की है ।
- झ) गैर-क्षतिकारक मूल्य का स्तर एक ऐसी सूचना है जो घरेलू उत्पादकों के लिए गोपनीय है क्योंकि यह स्तर, घरेलू उद्योग के उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में सभी संबद्ध घटकों के बारे में लागत निकालने की सूचना पर, आधारित होता है ।

2.5 थाइलैंड सरकार के विचार

विदेश व्यापार विभाग, थाइलैंड ने उल्लेख किया है कि कस्टम्स से निर्यात आंकड़ों की जांच करके यह पाया गया है कि याचिका में सूचीबद्ध दिए गए 3 कथित थाई निर्यातकों ने भारत को साइट्रिक एसिड का निर्यात नहीं किया है।

2.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स थाई साइट्रिक एसिड कम्पनी लि० थाइलैंड, मैसर्स एशिया साइट्रिक्स कम्पनी लि०, थाइलैंड और मैसर्स साइट्रिक एसिड इन्डस्ट्रीज लि० थाइलैंड ने एक न्यू शिपर रिव्यू के लिए पाटनरोधी नियमों के अनुसार आवेदन दायर किया है, यदि उन्होंने जांचाधीन अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु की बिक्री न की हो अथवा इसका निर्यात न किया हो।

सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के प्रति, प्रति - उत्तर

2.7 घरेलू उद्योग का उत्तर

क) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाईयों के प्रति कोई भी पक्ष शर्तात्मक निवेदन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक हितबद्ध पक्ष को निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए और उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बताए गए तरीके में आयातक प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के इस प्रकार के प्रस्ताव को, कुछ बातों के शर्ताधीन, असहयोगी मान सकते हैं।

ख) हितबद्ध पक्षों के इस निवेदन में कोई सार नहीं है कि अनंतिम शुल्क के पुष्टिकरण से एकाधिकारवादी स्थितियां पैदा होगी। यह तर्क अंतर्निष्ठ रूप से भ्रान्तिजनक है क्योंकि भारतीय उपयोगकर्ता, विभिन्न स्रोतों से विचारीधीन उत्पाद की अधिप्राप्ति कर रहे हैं और अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी भारतीय उत्पादक को एकाधिकारवादी बाजार स्थिति का लाभ हो रहा है।

ग) आयातक द्वारा उठाये गये इस तर्क कि पाटन का आरोप उस दशा में प्रमाणित नहीं है जब 1999-2000 और 2000-2001 में मैसर्स भारत स्टार्च बंद था, का कोई आधार नहीं है और इसे सीधे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि जांचावधि 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान भारत स्टार्च बंद था और अतः इसे घरेलू उद्योग के क्षेत्र में नहीं लिया गया था और अतः आयातक की शिकायत आधारहीन है।

घ) आयातक द्वारा अपुष्टिकर दावे किए गए हैं कि पाटन मर्जिन ओर क्षति आकलन के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं और इनकी व्यख्या नहीं की जा सकती। याचकाकर्ताओं के कुछ निवेदनों को आयातकों द्वारा इस आशय से लिया गया है और संदर्भ के वगैर उपयोग में लाया गया है कि वे यह दावा कर सकें कि ये साराणियां घरेलू उद्योग के बाजार अंश कमी आने के दावों का समर्थन नहीं करती हैं। इस बात से विशेषतौर पर इन्कार किया जाता है कि उत्पादन/उत्पादकता के आंकड़े, माने गए हैं और वास्तविक नहीं हैं। चूंकि उपर्युक्त तथ्यों के प्रति कोई तर्क नहीं उठाए गए हैं, अतः इस प्रकार, उस किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो मौजूदा जांचावधि के तथ्यों और परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

ड.) इंडोनेशिया और थाइलैंड के किसी भी निर्यातक ने मौजूदा जांचों में सहयोग नहीं किया है अतः प्रासंगिकी नियमों के तहत उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए सहयोग करने के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका असहयोग यह कि अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इंडोनेशिया के निर्यातक द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। निर्यात द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उन पूर्ण आंकड़ों के अभाव में जो या तो सीधे ही अथवा इंडोनेशिया के दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं,

प्राधिकार के पास मौजूदा नियम के तहत कोई अन्य विकल्प नहीं होगा कि वे उन्हें असहयोगी मानें। घरेलू उद्योग का यह निवेदन है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए निवेदन को विचार में न लिया जाए।

च) मैसर्स सिटुरजिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड ने इंडोनेशिया और थाईलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित साइट्रिक एसिड पर पाटमसेबी शुल्क के निर्धारण के लिए अपनी पूरी समर्थन प्रदान किया है।

छ) हमने इंडोनेशिया के निवेदनों पर विचार किया है और इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि प्रारम्भिक पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले पर्याप्त समय दिया गया था और प्रतिउत्तर के लिए पक्षों को पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी पर्याप्त समय दिया गया था।

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

2.8 आयातकों का प्रति-उत्तर

125

मैसर्स क्लेरियेन्ट (इंडिया) लिमिटेड

113919 1948 21.5

क) आयातकों ने यह बात उठाई है कि 456.67 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन को शुल्क को पाटन मार्जिन अथवा क्षति उन्मूलन स्तर पर आधारित किया जाता है और उन्होंने यह भी बात उठाई है कि यदि शुल्क को पूरे पाटन मार्जिन पर आधारित किया जाता है तो क्या क्षति उन्मूलन का स्तर उच्चतर नहीं होगा।

ख) याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य को स्थापित करने के लिए उत्पादन की अपनी स्वयं की लागत को भी शामिल किया है और यह बात भारत में घरेलू उद्योग की अक्षमता को परिलक्षित करती है।

ग) बनाई गई लागत के आधार पर पाटन का परिगणना करने के लिए स्रोत को प्रकट नहीं किया गया है।

घ) याचिकाकर्ता के अगोपनीय निवेदन जांचे हुए नहीं हैं।

१०. संस्कृत भाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित भाषाओं का स्थान बताइए-

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \\
 & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \\
 & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

- ड.) 1999-2000 अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता अपनी पूरी क्षमता पर प्रचालन कर रहे थे और वर्ष 2000-2001 में उनकी बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि कोई क्षति नहीं हुई है।

2.9 इंडोनेशिया के निर्यातक द्वारा मूल्य का वचन

मैसर्स पी0टी0 बुडी एसिड जया, इंडोनेशिया, जो साइट्रिक एसिड के उत्पादक और निर्यातक हैं, ने मौजूदा पाटन के मामले में निर्धारित प्रश्नावली में उत्तर नहीं दिया है, तथापि, 21 अक्टूबर, 2002 की सार्वजनिक सुनवाई के उपरान्त उन्होंने मूल्य के वचन का प्रस्ताव किया है।

2.10 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों पर गुणावगुण आधार पर और विश्व व्यापार संगठन समझौते की धाराओं के अनुरूप नियमों के अनुसार और सार्वजनिक सुनवाई के विभिन्न उपबंधों और अगोपनीय सूचना के प्रकटीकरण ब्यौरे जैसा कि पाटनरोधी नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

तथापि, याचिकाकर्ता/निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये हुए महत्वपूर्ण मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप से जांच की गई हैं-

- क) पाटनमार्जिन अथवा क्षति उन्मूलन स्तर की सीमा तक शुल्क संरचना के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं और प्रस्ताव करते हैं कि मार्जिन के बराबर अथवा इससे कम का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए, यह शुल्क यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करेगा।

- ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की लागत के बारे में आयातक/निर्यातक द्वारा उठाए गए अपुष्टिकर तथ्यों के बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लेखा पुस्तिका और रिकार्ड की पूरी और विस्तृत जांच और परीक्षा की है।
- ग) गैर क्षतिकारक मूल्य का स्तर एक ऐसी सूचना है जो घरेलू उत्पादकों के लिए गोपनीय है क्योंकि यह स्तर, घरेलू उद्योग के उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में सभी घटकों के बारे में लागत निकालने की सूचना पर, आधारित होता है।
- घ) मैसर्स क्लेरियान्ट (इंडिया) लि० द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में यह इंगित किया जाता है कि इसका ब्यौरा दिनांक 14 जून 2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा (ट)(1) का कालम (1) में प्रतिशत के संदर्भ में उसी कालम में आंकड़ों के लिए मीटरी टन में आयात नामक शीर्षक में दिया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कथित सारणी के अंत में आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है कि कालम-1 में उल्लिखित एम०टी० का संक्षेपक यह संकेत देने के लिए है कि यह सूची मीटरी टन में भौतिक मात्रा नापने के लिए की जा रही है न कि मूल्य नापने के लिए।

प्रारंभिक निष्कर्षों का पैरा ट(ख) के बारे में अंतिम कालम में टाइप की एक त्रुटि है क्योंकि पिछली सारणी का अंतिम कालम गलती से इस सारणी में टाइप हो गया प्रतीत होता है। अंतिम कालम में वास्तविक आंकड़े निम्न प्रकार से हैं-

| वर्ष | प्रतिशत शेयर |
|----------------------|--------------|
| 1999-2000 | 49.82% |
| 2000-2001 | 53.67% |
| अप्रैल- दिसम्बर 2001 | 44.42% |
| वार्षिकीकृत | 44.42% |

2.11 प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन दिये गये हैं -

मैसर्स सैटुरजिया बायोकेमिकल्स लिमि०

घरेलू उद्योग ने अपने पहले के निवेदनों में उल्लेख किया है कि क्योंकि न तो कोई प्रतिमूलात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं न ही विचाराधीन उत्पाद, समान प्रकार की वस्तु और घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है, अतः उन्होंने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रति या तो आयातकों/उपयोगकर्ता अथवा निर्यातक द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं किये गये

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातकों, आयातकों और याचिकाकर्ता द्वारा किये गये पूर्वोक्त निवेदनों की उस सीमा तक जांच की गई है जिस सीमा तक ये नियमों के अनुसार संगत हैं व मामले को प्रभावित करते हैं ।

3.1 विचाराधीन उत्पाद

प्राधिकारी दिनांक 14-6-2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों के विचाराधीन उत्पादन के बारे में पैरा (ड.)7 पैराग्राफ का निम्नानुसार, स्मरण करते हैं "मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद" साइट्रिक एसिड है जिसे एसिड मोनोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है । साइट्रिक एसिड एक मूलभूत रसायन है जिसे कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 के कस्टम उपशीर्ष

2918.14 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। कस्टम के वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वे जांच के कार्यक्षेत्र पर बंधनकारी नहीं हैं। साइट्रिक एसिड को खाद्य, साफ्ट ड्रिंक्स, कनफैक्सनरी, ड्रग्स, में पर्सपेक्टिव के रूप में टैक्सटाइल डाइंग और मुद्रण उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। इसके अन्य औद्योगिक उपयोग भी हैं जैसे कि वायलर क्लीनिंग, आदि। चूंकि हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई तर्क नहीं उठाये गये थे, अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादन के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

3.2 समान प्रकार की वस्तु

प्राधिकारी, दिनांक 14-6-2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों के समान वस्तुओं के पैराग्राफ (च) 8 का निम्नानुसार स्मरण करते हैं-

पाटनरोधी नियम का नियम 2(घ) निर्दिष्ट करता है कि समान प्रकार का तात्पर्य उस वस्तु से है जो जांचाधीन उत्पाद के लिये सभी प्रकार से समरूप अथवा समान हो अथवा इस प्रकार की वस्तु की अनुपस्थिति में वह दूसरी वस्तु जिसकी विशेषताएं, जांचाधीन वस्तु से नजदीकी रूप से मिलती-जुलती हों। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित साइट्रिक एसिड जिसका आयात संबद्ध देशों से किया जा रहा है, को अदल-बदल कर उपयोग में लाया जा सकता है और इस प्रकार ये दोनों उत्पाद वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और अतः नियमों के अर्थ के भीतर समान प्रकार की वस्तु हैं।

इस बात पर विवाद के लिये कोई तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित साइट्रिक एसिड की विशेषताएं, आयातित उत्पाद से नजदीकी तौर पर मिलती-जुलती है और इन्हें वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों तौर पर संबद्ध देशों से आयातित साइट्रिक एसिड द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित साइट्रिक एसिड को नियम 2(घ) के अर्थ के तहत थाईलैंड और इंडोनेशिया से निर्यातित उत्पाद के लिये समान प्रकार की वस्तु माना गया है।

हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये गये किन्हीं भी तर्कों की अनुपस्थिति में प्राधिकारी ने समान प्रकार की वस्तुओं के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की है।

3.3 घरेलू उद्योग की स्थिति

घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में प्राधिकारी दिनांक 14-6-2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों के पैराग्राफ (छ) 9 का निम्नानुसार स्मरण करते हैं -

घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स सिटुरजिया बायोकैमिकल्स लिमि0 द्वारा याचिका दायर की गई है। भारत में साइट्रिक एसिड के अन्य उत्पादक मैसर्स भारत स्टार्च इन्डस्ट्रीज लिमि0 हैं। तथापि, मैसर्स भारत स्टार्च इन्डस्ट्रीज लिमि0 वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में बंद पड़ी हुई थी और उनका साइट्रिक एसिड संयंत्र केवल दिसम्बर 2001 के तीसरे सप्ताह में ही शुरू हो पाया। अतः मैसर्स सिटुरजिया बायोकैमिकल्स लिमि0 का घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी नियमों के अनुसार याचिका दायर करने का हक बनता है।

पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग का तात्पर्य समग्रतौर पर उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान प्रकार की वस्तु अथवा इससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं अथवा जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अंश होता है सिवाय उस दशा के जब इस प्रकार के उत्पादक कथित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, ऐसी दशा में इस प्रकार के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जायेगा।" इसके अलावा, पाटनरोधी नियमों का नियम 5(3) उल्लेख करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (i) के तहत किये गये आवेदन के अनुपालन में तब तक किसी भी जांच की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक आवेदन के प्रति समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किये गये समर्थन अथवा विरोध के आधार पर यह निर्धारित न

हो जाए कि यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई। इसमें यह भी व्यवस्था है कि कोई जांच नहीं की जायेगी यदि घरेलू उत्पादकों की संख्या घरेलू उद्योग द्वारा समान प्रकार की वस्तु के लिये कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम बैठती है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी घरेलू उत्पादकों द्वारा याचिका का विरोध नहीं किया गया है और अतः किसी भी निवेदनों के प्राप्त न होने की बात को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह मत बनाते हैं कि याचिकाकर्ता नियम 5(3) और (ख) के अनुसार शर्तों को पूरा करते हैं और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3.4 मूल्य बचनबद्धता

मूल्य बचनबद्धता के बारे में जांच को स्थगित व समाप्त करने के बारे में पाटनरोधी नियमों के नियम 5 में व्यवस्था दी गई है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी जांच को स्थगित व समाप्त कर सकते हैं यदि प्रश्नाधीन संबंध वस्तु के निर्यातक, प्राधिकारी को लिखित में मूल्यों को संशोधित करने का वचन देते हैं जिससे कि संबंध वस्तु का भारत में पाटन मूल्यों पर निर्यात न किया जा सके अथवा विशिष्ट देशों से आयात किये जाने की दशा में मूल्यों को संशोधित करने का वचन दें ताकि पाटन के क्षतिकारक प्रभावों को दूर किया जा सके और निर्दिष्ट प्राधिकारी को सतोष हो जाए कि पाटन के क्षतिकारक प्रभाव दूर हो गये हैं।

मैसर्स पी0टी0 बुडी एसिड जया, इंडोनेशिया

एक निर्यातक मैसर्स पी0टी0 बुडी एसिड जया इंडोनेशिया ने मूल्य के संबंध में वचन देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। इस प्रस्ताव की विस्तृत तौर पर जांच की गई और नामित प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातक द्वारा प्रस्तावित वचनबद्धता को स्वीकार नहीं किया जा

सकता क्योंकि मैसर्स पी0टी0 बुडी एसिड जया ने निर्यातक प्रश्नावली के प्रति पूरा उत्तर दायर नहीं किया और अतः उसे प्राधिकारी द्वारा जांचावधि के दौरान असहयोगी माना गया ।

3.5. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डम्पिंग मार्जिन

9 क (1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान सामान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या
- (ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष दशा के कार अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रीयों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-
 - (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ;

"अर्थात् कि वस्तु का आयात जब मूलतः के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित

नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।"

3.6 इंडोनेशिया

क सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार पूरी सूचना नहीं दी है ।

याचिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का, साइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिये बनाई गई लागत के आधार पर जांचों के प्रारंभिक निष्कर्षों के समय, निर्धारण किया गया था । प्राधिकारी ने, अंतिम निष्कर्षों के लिए इसी को अपनाया है । तदनुसार, इंडोनेशिया से सभी निर्यातकों के लिए साइट्रिक एसिड का सामान्य मूल्य, ***** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन लिया गया है ।

(ख) निर्यात मूल्य

इंडोनेशिया से किसी भी निर्यातकों ने निर्यात मूल्य के बारे में प्रश्नावली में विस्तृत विवरण नहीं दिया है । प्राधिकारी ने डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक जांच के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण स्वीकार किया है । प्राधिकारी ने अन्तिम निष्कर्ष हेतु वही तरीका अपनाया है । याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अन्तर्देशीय और बन्दरगाह भाड़े के लिए क्रमशः ***** और अमेरिका डालर ***** सीमा तक समयोजनों का दावा भी स्वीकार किया है । जांच अवधि में एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य इस प्रकार ***** अमेरिकी डालर/मीटरी टन बैठता है ।

3.7 थाईलैण्ड

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि थाईलैण्ड से किसी भी निर्यातक/उत्पादकों ने प्रश्नावली द्वारा निर्धारित सूचना के अनुसार विवरण नहीं दिया है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का, साइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए बनाई गई लागत के आधार पर जाचों के प्रारंभिक निष्कर्षों के समय निर्धारण किया गया था। प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्षों को उसी रूप में अपनाया है । तदनुसार जापान के सभी निर्यातकों से साइट्रिक एसिड के लिए सामान्य मूल्य ***** अमेरिकी डालर/प्रति मीटरी टन में लिया गया है ।

(ख) निर्यात मूल्य

इंडोनेशिया से किसी निर्यातक ने निर्यात मूल्य में प्रश्नावली के विस्तृत विवरण नहीं दिया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता से प्राप्त किये गये आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक जांच के लिये निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है । याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बन्दरगाह के व्ययों और अन्तर्देशीय भाड़े के लिये क्रमश ***** , ***** , ***** और अमेरिकी डालर ***** सीमा तक क्षमयोजनों का दावा भी स्वीकार किया है । जांच अवधि में एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य इस प्रकार ***** अमेरिकी डालर/मीटरी टन बैठता है ।

3.8 पाटन - सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना

क. तुलना से संबंधित नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई -

- (i) पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय नामित प्राधिकारी, निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य से तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर और सामान्यतया एक्स वर्क्स स्तर पर और जहां तक संभव हो लगभग उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में की जायेगी।
- (ii) प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण आधार पर उन अन्तरों के लिए छूट दी जाएगी जिनसे बिक्री की शर्तों, कर प्रणाली, व्यापार के स्तरों, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अन्तर और किन्हीं अन्य अन्तरों में जो मूल्य की तुलनात्मकता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, के सहित मूल्यों की तुलनात्मकता प्रभावित होती है।
- (iii) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन जैसाकि पाटनरोधी नियमों के संलग्नक -1 में दिया गया है, को अधिशासित नियमों को अनुपालन करने का प्रस्ताव किया है। ऊपर यथा उल्लिखित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबंधित देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के मामले में पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे की सारणी के अनुसार किया है -

| देशवार निर्यातक/ उत्पादक | सामान्य मूल्य (अमेरिकी डालर/मीटरी टन) | निर्यात मूल्य (अमेरिकी डालर/मीटरी टन) | पाटन मार्जिन (%) |
|--------------------------------|--|--|---------------------|
| इण्डोनेशिया | **** | **** | 70.95% |
| थाईलैण्ड | **** | **** | 55.08% |

घ 4.1 क्षति और कारणात्मक संबंध

उपर्युक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने में पाटित आयातों की मात्रा, समान प्रकार की वस्तु के लिए घरेलू बाजार में उनके मूल्यों पर प्रभाव और इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामात्मक प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण किया जाना शामिल होगा। चालू मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में इस बात की जांच की जानी आवश्यक है

कि भारत में समान प्रकार की वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में काफी कमी हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है।

4.2 क्षति का सकल आकलन

रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रत्येक संबद्ध देशों से पाटन का मार्जिन 2% की सीमा से अधिक था जिसे निर्यात मूल्य की % प्रतिशतता में व्यक्त किया गया है। आयातों के प्रभाव का सकल आकलन किया जाना उचित होगा, क्योंकि संबद्ध देशों से किए जाने वाले निर्यात भारत में सीधे ही एक दूसरे से और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः प्राधिकारी, संकल तौर पर संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को आंकने का प्रस्ताव करते हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा उपर्युक्त दी गई सीमा से अधिक है। आयातों के प्रभावों का सकल आकलन और थाइलैंड देशों से निर्यात मूल्य का प्रभाव पड़ता है और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा पेश किये गये मूल्य के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।

4.3 पाटन रोधी नियम के संलग्नक-II के सिद्धान्त (IV) में पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव के सबन्ध में दिया है:-

"पाटित आयातों से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच की जिसमें सभी संबंधित आर्थिक कारणों का मूल्यांकन, राज्य के उद्योग के उत्पादन के संकेत, बिक्री में कमी होने के प्राकृतिक एवं सम्भावित कारण लाभ, उत्पादन, मार्केट शेयर, उत्पादकता निवेश के बारे में, उपयोग क्षमता घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण, वास्तविक पाटन के मार्जिन की मात्रा, कैश फ्लो इन्वेन्ट्रीज रोजगार मजदूरी में वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि की योग्यता, शामिल है।"

- 4.4 उपर्युक्त बातों को नोट करने के पश्चात प्राधिकारी यह विचार बनाते हैं कि संबंधित उत्पादों से बिक्री प्राप्ति पर उचित तौर पर विचार करके विभिन्न घरेलू उत्पादकों के लिये क्षति रहित मूल्य का आकलन किया गया है। इसके अलावा, अक्षमताओं को दूर करने में प्राधिकारी ने कच्चे माल, उपयोगी वस्तुओं आदि के उपयोग के बारे में सबसे अच्छी पद्धतियों को मापदंड बनाया।
- 4.5 उस क्षति के बारे में जो भारत के उत्पादन के उच्चतर लागत के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के तहत यह कमतर शुल्क नियम है जिसे लागू किया जाता है। इसके अलावा पाटन रोधी शुल्क किसी भी दशा में पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता। अतः किसी की दशा में यदि घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति होती है जो पाटन मार्जिन से अधिक हो, उसे निश्चयात्मक रूप से पाटनरोधी नियमों के तहत नहीं देखा जा सकता।
- 4.6 प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्षों के लिए क्षति संबंधी सभी संकेतों को लिया है। इसमें सभी संबंधित मापदण्ड शामिल होंगे अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, उनका घरेलू बाजार में मूल्यों पर प्रभाव और घरेलू निर्माताओं, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, कुल बिक्री प्राप्ति आदि पर पड़ने वाले तदन्तर प्रभाव। घरेलू उद्योग के लिए समान प्रकार की वस्तु के लिए अक्षतिकारक मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की एक ऐसी इष्टतम लागत पर विचार किया, जो सर्वोत्कृष्ट प्रतिमानित खपत मानकों को ध्यान में रखेगा और जांचाधीन अवधि के दौरान ऐसे कच्चे माल जिनका उपयोग जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में होता है, के वास्तविक मूल्यों को भी ध्यान में रखेगा। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी, एक अक्षतिकर मूल्य पर इष्टतम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हैं।

प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम के अनुबंध-II के अनुसार क्षति के विभिन्न मापदण्डों की भी जांच की है और उन्होंने क्षति को स्थापित करने की दृष्टि से उन विभिन्न तथ्यों को भी देखा जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे।

- 4.7 संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई मौजूदा क्षति को नीचे पैरामीटरों में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिखाया गया है:-

क. भारतीय उत्पादकों द्वारा मार्केट शेयर में किये गये परिवर्तन

प्राधिकारी नीचे दिये गये सारणी से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी का संबंध वैसा ही है जैसे कि देश में कुल मांग का है। जांच अवधि के दौरान मार्केट शेयर में 2000-2001 में 53.67 से 44.42 प्रतिशत कमी हुई है। मार्केट शेयर में अधिक कमी आई है जैसा कि कुल मांग में दर्शाया गया है।

| वर्ष | घरेलू बिक्री | कुल मांग | शेयर % |
|--------------------|--------------|----------|--------|
| 1999-2000 | 100.00 | 100 | 49.82% |
| 2000-2001 | 104.68 | 97 | 53.67% |
| अप्रैल-दिसंबर 2001 | 68.57 | 77 | 44.42% |
| वार्षिकीकृत | 91.42 | 103 | 44.42% |

अनुक्रमण

यह पाया गया है कि संबंधित देशों से आयातों की तुलना 2000-2001 में बढ़ रहे कुल आयात से 27.78 प्रतिशत से 75.28 प्रतिशत अधिक बढ़ा है।

जांच की अवधि के दौरान। यह वृद्धि इन स्रोतों से आयातों के कम मूल्य होने के कारण है। संबद्ध देशों से होने वाली आयातों में अचर रूप से भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण घरेलू उद्योग के बाजार अंश की हानि हुई है।

| वर्ष | संबद्ध देशों से आयात (मीटरी टन) | कुल आयात | % शेयर |
|--------------------|------------------------------------|----------|---------|
| 1999-2000 | 100.00 | 100.00 | 9.68 % |
| 2000-2001 | 257.40 | 89.72 | 27.78 % |
| अप्रैल-दिसंबर 2001 | 662.39 | 85.19 | 75.28 % |
| वार्षिकीकृत | 883.19 | 113.59 | 75.28 % |

इसके अलावा, देश में कुल मांग की तुलना में संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में भी काफी वृद्धि हुई है और यह 1999-2000 के 4.86 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 12.87 प्रतिशत और जांचावधि के दौरान 41.84 प्रतिशत हो गई है।

| वर्ष | आयात (मीटरी टन) | कुल मांग | % शेयर |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1999-2000 | 4.86% | 100.00 | 4.86% |
| 2000-2001 | 12.87% | 97.18% | 12.87% |
| अप्रैल-दिसंबर 2001 | 41.84% | 76.91% | 41.84% |
| वार्षिकीकृत | 41.84% | 102.54% | 41.84% |

ख. उत्पादन/उत्पादकता और क्षमता उपयोग

यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान से पहले क्षमता उपयोग के काफी उच्च स्तरों पर प्रचालन कर रहा था। तथापि याचिकाकर्ताओं की क्षमता उपयोग 2000-2001 में 98.59 प्रतिशत से घटकर जांचाधीन अवधि में 94.60 प्रतिशत घटकर रह गया, जो इस अवधि में लगभग 4 प्रतिशत कमी को दर्शाती है। यह भी देखा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जांचाधीन अवधि में उत्पादन में कुछ कमी आई है।

| वर्ष | क्षमता (मीटरी टन) | उत्पादन (मीटरी टन) | उपयोगी क्षमता (%) |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1999-2000 | 100 | 100.00 | 97.79 % |
| 2000-2001 | 100 | 100.82 | 98.59 % |
| अप्रैल-दिसंबर 2001 | 75 | 72.55 | 94.60 % |
| वार्षिकीकृत | 100 | 96.73 | 94.60 % |

ग. बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य

प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में इस जांच अवधि के दौरान 12.7 प्रतिशत तक की काफी कमी आई है। यह देखा जा सकता है

कि पिछले वर्ष से इस जांच अवधि में बिक्री मूल्य में भी कमी आई है। यद्यपि बिक्री मूल्य में कमी मामूली है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि इस अवधि में घरेलू उद्योग ने बिक्री में काफी हानि उठाई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि बिक्री मूल्य का वही स्तर बनाए रखने का घरेलू उद्योगों का प्रयास कम हो रही बिक्री मात्रा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संबद्ध देशों से निरंतर पाटन के कारण घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु सामान की बिक्री पर हानि उठानी पड़ रही है।

घ. खोई संविदाओं का साक्ष्य

शिकायतकर्ता घरेलू उद्योग ने आग्रह किया है कि ग्राहकों को रोके रखने के उनके प्रयासों के बावजूद यह तथ्य कि पाटन किया गया 3670 मी.टन आयात भारत में जांचावधि के दौरान हुआ, इस बात का पर्याप्त प्रभाव है कि इसने ग्राहकों की क्षमता खो दी है।

ड. रोजगार एवं मजदूरी

घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि कम उत्पादन के बावजूद उन्होंने वृहत स्तर पर उत्पादन और क्षमता समुपयोजन बनाए रखने के सभी प्रयास किए हैं, इसलिए रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को हुए नुकसान रोजगार के आँकड़ों में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि भारतीय श्रमिक कानून इस बारे में सख्त हैं। उपर्युक्त इन कारणों से मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

च. लाभ प्रदता

कुछ आयातकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की लागत और लाभप्रदता और घरेलू उद्योग की अक्षमता का सावधानीपूर्वक और सम्यक रूप से

जाँच पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, प्रत्यायोजित प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी विरोधी पक्षों ने अपने दावे स्थापित करने के लिए कोई ठोस आँकड़ा या निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। निर्यातकों/आयातकों द्वारा दिए गए अप्रमाणिक तर्कों के बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दस्तावेजों और रिकार्डों का पूर्ण एवं विस्तृत जांच पड़ताल के आधार पर प्राधिकारी इस संबंध में प्रारम्भिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है। जैसा कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में दर्शाया गया है, घरेलू उद्योग को प्रति यूनिट बिक्री के प्रत्यक्ष हानियों के रूप में काफी नुकसान हुआ है। जाँच की अवधि के दौरान उत्पादित प्रति यूनिट उत्पादन के विक्रय मूल्य और लागत के बीच तुलना से प्रति यूनिट बिक्री में हानि में वृद्धि दिखाई पड़ती है। प्रारम्भिक निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि केवल मूल्य कारक से ही घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई।

| वर्ष | बिक्री मूल्य (लाख रु. में) | बिक्री की लागत (लाख रु. में) | लाभ/हानि (लाख रु. में) | लाभप्रदता |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1999-2000 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2000-2001 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| अप्रैल-दिसंबर 2001 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| वार्षिकीकृत | ***** | ***** | ***** | ***** |

छ. नकदी प्रभाव और संबंधित पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव

जैसाकि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को जांचावधि के दौरान हानि हुई है जिसके कारण जो स्पष्टतया उनका नकदी प्रभाव को प्रभावित कर रही है। उद्योग में हानि के कारण और स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग विस्तार के लिये कोई नये निवेश करने की स्थिति में भी नहीं हैं।

ज. सामान सूची

सामान सूची में काफी वृद्धि हुई है और यह मार्च 2001 के अंत के 687 मीटरी टन से बढ़कर 31-12-2001 को 1225 मीटरी टन हो गई और अतः यह घरेलू उद्योग को क्षति होने का संकेतक है ।

झ. पाटन के मार्जिन की मात्रा -

जैसे कि पहले ही इन निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफों में निर्दिष्ट किया गया है कि इंडोनेशिया और थाइलैंड के लिये पाटन का मार्जिन क्रमशः 71.95 प्रतिशत और 55.08 प्रतिशत है ।

ञ. मूल्य में कमी

यह माना गया है कि संबद्ध देशों द्वारा किए जा रहे पाटन से घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु के लिए बिक्री प्राप्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है । अपने बाजार को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं को सम्बद्ध वस्तुओं से कम किए गए मूल्यों और पाटन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है । पाटित आयातों की पहुंच मूल्य भी मूल्यों में कमी की ओर संकेत कर रही है ।

ट. कम मूल्य पर बेचना

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे की जांच की है कि घरेलू उद्योग को सीधी क्षतियों के कारण हानि हुई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति को आंकने के लिए मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करना एक महत्वपूर्ण संकेतक है । प्राधिकारी ने एक उचित बिक्री मूल्य तैयार

किया है और कम मूल्य पर बिक्री मूल्य का निर्धारण करने के लिए उसकी मूल्य के साथ तुलना की है।

ठ) निवेश पर प्रतिफल और पूंजी पैदा करने की क्षमता

घरेलू उद्योग के लिये विचाराधीन उत्पाद के लिये जांचावधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल की दर नकारात्मक रही है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग इस उत्पाद के लिये नई पूंजी पैदा नहीं कर पाया है अथवा नये निवेशों की आयोजना नहीं कर पाया है।

ड. कारणात्मक संबंध

5.1 यह निर्धारित करने के लिए क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई थी, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा:-

- (क) प्राधिकारी ने यह भी देखा कि सम्बद्ध वस्तुओं के लिए केवल एक ही बाजार है, जहाँ पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः मांग में कमी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारण नहीं है। आयातित सम्बद्ध सामान और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं समान प्रकार की मर्दे हैं और उन्हें समान उद्देश्यों/प्रयोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण की बात आयातित स्रोतों से अथवा घरेलू स्रोतों से समान की खरीददारी का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।
- (ख) सम्बद्ध देशों से किए गए आयातों से भारतीय बाजार में उत्पादों के मूल्यों को इस सीमा तक कम किया है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की लागत को वसूल नहीं कर पाया है और भारत में सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री से एक औचित्यपूर्ण लाभ नहीं ले पाया है।
- (ग) पाटित मूल्यों पर संबद्ध देशों से काफी मात्रा में आयातों से घरेलू उद्योग को हानियां हुईं।

5.2 प्राधिकारी ने विभिन्न आर्थिक तथ्यों एवं संकेतों की जाँच की और निम्नलिखित निष्कर्षों में पहुँचे:-

1. संबंधित देशों से सम्बंधित वस्तुओं के पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है ।
2. पाटित आयातों से संबंधित वस्तुओं के घरेलू मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मूल्यों में कमी हो रही है ।
3. संबंधित वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण मूल्यों में कमी करनी पड़ रही है ।
4. घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तुओं की सूची में पाटित आयातों के कारण वृद्धि हो रही है ।
5. घरेलू उद्योग की बाजार में मार्केट मांग पूरी तरह से समाप्त हो गई है ।
6. घरेलू उद्योग नये सिरे से पूंजी बढ़ाने (लगाने) और नये निवेश की योजना बनाने में समर्थ नहीं है ।
7. घरेलू उद्योग अपने कर्मचारियों को वेतन देने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है ।

घरेलू उद्योग को उपयुक्त कारणों से भौतिक क्षति हुई है ।

च. भारतीय उद्योग का हित और अन्य विषय

- 6.1 प्राधिकारी यह भी विचार रखते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य साधारणतया पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षतियों को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्बहाली हो सके, जो देश के आम हित में है ।
- 6.2 प्राधिकारी इस बात को भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु का उपयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप यह इन उत्पादों की सम्बन्धात्मक प्रतिस्पर्धाओं पर कुछ असर डाल सकता है, तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं हो पाएगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ

को दूर किया जा सकेगा और इससे घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना, संबद्ध देशों से होने वाले आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और अतः इससे उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

छ. अंतिम निष्कर्ष

7.1 उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात यह देखा जाता है:-

- (क) इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड मूल के अथवा वहाँ से साइट्रिक एसिड का भारत को निर्यात करने के कारण सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया।
- (ख) इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड से संबद्ध वस्तुओं का अधिक आयातों के पाटन से मूल्यों में कमी आ रही है और मूल्यों को कम करना पड़ रहा है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है।
- (ग) इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है।

7.2 इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड मूल के अथवा वहाँ से साइट्रिक एसिड के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का विचार किया है।

7.3 प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क को राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिका का कंपनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है।

- 7.4 प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इंडोनेशिया और थाईलैण्ड मूल के अथवा वहां से निर्यातित साइट्रिक एसिड के संबंध में जैसा कि कॉलम-3 में नीचे संकेत दिया है उन सभी पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

| क्र०सं० | निर्यातक/उत्पादक | सिफारिश की गई पाटन रोधी शुल्क की राशि (अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन) |
|-------------|----------------------|--|
| 1. | 2. | 3. |
| इण्डोनेशिया | सभी निर्यातक/उत्पादक | 456.67 |
| थाईलैण्ड | सभी निर्यातक/उत्पादक | 374.36 |

- 7.5 इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क विग द्वारा निर्धारित आंकलन योग मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार शुल्क शामिल होंगे ।
- 7.6 उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी 14.6.2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।
- 7.7 उक्त अधिनियम के अनुसार इस आदेश के खिलाफ सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2003

Final Findings

No. 14/11/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:-

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Citurgia Biochemicals Ltd., on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Citric Acid (hereinafter referred to as subject good) originating in and exported from Indonesia and Thailand (hereinafter referred to as subject countries);

ii) The Authority notified the Embassy/High Commission of the subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;

iii) The Authority issued a Public Notice dated 16th April, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Citric Acid originating in or exported from the subject countries falling under Customs Sub-heading 2918.14 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. :

iv) The Authority notified preliminary findings dated 14.6.2002 and forwarded a copy of the preliminary findings to the following interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter:-

IMPORTERS/USER

1. M/s Amijal Chemicals, Mumbai
2. M/s Jain Process Foods Ltd., Jalgaon

3. M/s Posy Pharmachem P. Ltd., Ahmedabad
4. M/s C.J. Shah & Co., Mumbai
5. M/s Cipla Ltd., Pune
6. M/s Jain Process Foods Ltd., Jalgaon
7. M/s Sunil Chemicals, Virar, Distt. Thane
8. M/s Clariant(India) Ltd., Thane.
9. M/s Parle International Ltd., Mumbai

EXPORTER

1. M/s Pt Budi Acid Jaya Tbk, Indonesia
2. M/s Thai Citric ACid Co.Ltd., Thailand
3. M/s Asia Citrix Co. Ltd., Thailand
4. M/s Citric Acid Industry Ltd., Thailand

DOMESTIC INDUSTRY

M/s Citurgia Biochemicals Ltd

- v) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject country in New Delhi with a request that the exporters of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings within forty days of the date of the letter.
- vi) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 21.10.2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.
- vii) Submissions in response to the preliminary findings/public hearing were made by the following interested parties:-
 - a) M/s Citurgia Biochemicals Ltd.,
 - b) M/s Clariant (India) Ltd
 - c) M/s Bilt Biochemicals Ltd.,
 - d) Views of Govt. of Indonesia on behalf of exporter
 - e) Views of Govt. of Thailand on behalf of exporter

- viii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- ix) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
- x) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the disclosure and/or these findings;
- xi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 11.12.2002 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.
- xii) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner. The cost data of the following domestic producer was provided and analysed:--

1. **M/s. Citurgia Biochemical Ltd.,**

- xiii) The Authority verified the information provided by the petitioners to the extent considered necessary.
- xiv) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xv) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 31st December 2001 i.e. the period of investigation (POI).

B. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

2.1 VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY

- a) The margin of dumping from the subject countries has also been evidenced by the petitioner to be more than the 2% limit expressed as % of export price. It is an admitted position that the volumes of imports from the subject countries is more than the de-minimus, and the margin of dumping based on the constructed cost method as 70.95% and 55.08% for Indonesia and Thailand respectively.
- b) The present petition filed by the domestic industry should be seen in the light of the severe injury suffered by the domestic industry

due to indiscriminate dumping by the exporters. The performance of the domestic industry should also be seen in the light of severe dumping resorted by the exporters from the subject countries.

It is evident that the quantum of imports from each of the subject country is more than the de-minimus limit. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject countries directly compete with the prices offered by the domestic industry in the Indian market. Therefore, the domestic industry has requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.

Material injury is being caused to domestic industry from imports. The domestic industry is producing the subject goods for the past many years. The technology adopted by the domestic industry is comparable to the technology adopted by other players. Dumped prices by the exporters from subject countries is the sole reason for the present state of market in India.

- c) None of the exporters has responded in the prescribed format to assist the Hon'ble Designated Authority to work out the dumping margins. It is therefore fairly clear that the exporters from the subject countries are aware of the fact that they are exporting the subject goods to India at dumped prices.
- d) Since there has been no response either from the importers or the exporters subsequent to the preliminary findings, it is presumed that they have no comments to offer. Under the circumstances, we would request the Hon'ble Designated Authority to kindly confirm the preliminary findings at the earliest.
- e) M/s. Bilt Biochemicals Ltd., installed capacity is 25000 MT per annum in addition to the installed capacity of M/s. Citurgia Biochemicals Ltd., of 6000 MT per annum. The domestic demand for citric acid is approximately 11000-12000 MT per annum, therefore, it is obvious that the domestic production far outstrips domestic demands, and if citric acid is allowed to be dumped into the country the domestic industry will suffer irreparable damage making it difficult to operate.

2.2 VIEWS OF IMPORTERS

M/s. Clariant (India) Ltd.,

- a) The petition filed by the complainant itself mentions that M/s. Bharat Starch was closed in the years 1999-2000 & 2000-2001 and recommissioned their Citric Acid plant only in the 3rd Week of

December 2001. It is surprising that there is an allegation that there is dumping on one hand and at the same time the initiation notification states that M/s. Bharat Starch which is the other producer of Citric Acid was closed during the period of investigation. This allegation of domestic industry of dumping is unsustainable.

- b) Without providing the adequate and substantial details such as cost of production, etc. will be a handicap as, we as importers, will be unable to meet and demonstrate our contention without knowing whether the allegation of dumping is true or not.
- c) Without prejudice the figures given by the complainant regarding the dumping margins and injury assessment are inaccurate and cannot be explained as at one hand the imports are being quantified in terms of MT, at the same time they are shown as percentage. It has also been mentioned in the injury assessment that the market share of domestic industry declined inspite of the total demand showing an upward trend, but the table does not show this picture. The Output/Productivity figures are also not acceptable because it seems that they have been assumed & not actual.
- d) M/s. Clairant (India) Ltd., imports 12MT/month of Citric Acid for manufacturing of textile chemicals. They procure Citric Acid both from the Petitioner Company and M/s. Bharat Starch.
- e) The importer has apprehended, if the provisional duty is confirmed these two major manufacturer of citric acid in India will lead to a complete monopolistic situation as anti dumping duty is already imposed on imports from China.

2.3 VIEWS OF GOVERNMENT OF INDONESIA

- a) The Indonesian Government has requested the Authorities to re-examine the allegation of dumping once the deficiencies are removed by the Indonesian Exporter.
- b) The Indonesia Government wanted to know whether the duty of US\$ 456.7 is based on full dumping margin or the injury elimination level which is not clear from recital 24 of the finding. They further stresses whether the duty is based on the injury elimination on full dumping margin the non-injurious price calculation will be the highest in the World for citric acid.
- c) They have stated that because of the level of inefficiency of the domestic manufacturer in India, their cost of production may be

higher or petitioner might have probably inputted their own cost of production to establish the normal value.

- d) Article 3.4 of the WTO Agreement requires all the known factors be considered in determining whether injury is attributable to the dumped imports.
- e) The domestic industry produces other goods as well as Citric Acid. In this regard, it is important for Designated Authority to take account of whether the alleged injury is attributable to the performance of the company in other sectors.
- f) The Government of Indonesia has difficulty in defending its interest as high level of confidentiality is granted to the petitioner and the non-confidential submission of the petitioner is unverified.
- g) There is no justification not to provide source for the cost of production information used to establish normal value so in the light of Article 6.5.2 of the WTO Agreement the Designated Authority is required to disclose the source of information used and the actual value of the indices presented.
- h) The petitioner has been operating at the full capacity during 1999-2001. In the year 2000-2001 the petitioner has shown a increase in both sales volume and selling price where as sales volume in the investigating period has declined but selling price was maintained, as such there is no evidence of price depression with the unit selling prices.
- i) The applicant did not wish to include the other Indian producer, in the proceeding as their could be many reasons as lack of support from the other Indian producer who may have confidence of the Citric Acid market in future.

2.4 **EXAMINATION BY THE AUTHORITY ON VIEWS EXPRESSED BY GOVERNMENT OF INDONESIA**

- a) The Authority notes that the Indonesian Exporter did not file the complete response to the exporters questionnaire. This issue was addressed at the Para 11 in the preliminary findings.
- b) Regarding the duty composition to the extent of dumping margin or injury elimination level, the Authority proposes to recommend the anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

- c) The exporter has not furnished the complete data regarding cost of production in the relevant Appendix of the exporters questionnaire as pointed out in Para 11 (C) of the preliminary findings. The Authority has therefore been constrained to determine the cost of production and normal value as per facts available.
- d) All factors have been examined to ascertain the impact of dumped imports on the domestic industry.
- e) The Authority notes that only the costing and factors related to the Injury in production of Citric Acid have been taken into consideration in this investigation.
- f) The Authority notes that the non-confidential submission of the petitioner has been forwarded to the Exporters along with the initiation notification dated 16th April 2002 in the light of Rule 6 and Rule 7 of Anti Dumping Rules.
- g) The Authority notes that there is a significant decline both in sales volume and selling price of the domestic industry during the period of investigation. While the decline in selling price is marginal but it is important to note that the domestic industry has lost significant sales during the POI and it is because the domestic industry's attempt to maintain the same level of the selling price.
- h) The Authority notes, regarding cost of production, the authority carried out the complete and detailed verification and examination of the books of accounts and records of the domestic industry.
- i) The level of non-injurious price is the information confidential to the domestic industry as the level is based on the costing information on all relevant factors concerning the production and the production process of the domestic industry.

2.5 **VIEWS OF GOVERNMENT OF THAILAND**

Department of Foreign Trade, Thailand has stated while investigating export statistics from customs it has found that the 3 alleged Thai exporters listed in the petition have not exported Citric Acid to India.

2.6 **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

The Authority notes that the exporters M/s. Thai Citric Acid Co. Ltd., Thailand, M/s. Asia Citrix Co. Ltd., Thailand and M/s. Citric Acid Industry Ltd., Thailand may file application as per anti dumping rules for a New Shipper Review if they have not sold or

exported the subject merchandise to India during the period of investigation.

REJOINDER TO THE SUBMISSIONS MADE BY THE INTERESTED PARTY IN THE PUBLIC HEARING:

2.7 REJOINDER OF DOMESTIC INDUSTRY

- a) A party to the proceedings before the Hon'ble Designated Authority cannot and should not make conditional submissions. Each interested party is expected to cooperate with the Designated Authority and must furnish information as per importers questionnaire in the form and manner specified by the Hon'ble Designated Authority. It is requested that the Hon'ble Designated Authority may treat such offers of making available requisite information subject to conditions as an attitude of non-cooperation.
- b) There is no substance in the submission of the interested parties that confirmation of provisional levy would result in monopolistic situation. The argument is inherently fallacious as the Indian users are procuring the product under consideration from multiple sources and, therefore, it cannot be said that any Indian producer is enjoying monopolistic market conditions.
- c) The argument raised by the importer that allegation of dumping is unsustainable when M/s. Bharat Starch was closed for years 1999-2000 and 2000-2001 is without any basis and deserves to be rejected outright. It is admitted that Bharat Starch was closed as pointed out during the period 1999-2000 & 2000-2001 and hence was not taken within the purview of domestic industry and therefore the grievance of the importer is baseless.
- d) Unsubstantiated claims have been made by the importer that the figures given by the complainant regarding the dumping margins and the injury assessment are inaccurate and cannot be explained. Certain submissions of the Petitioners have been picked up and used out of context by the importer to claim that the tables do not support submissions of drop in market share of domestic industry. It is specifically denied that output/productivity figures are assumed and not actual. Since there is no argument raised against the above mentioned facts, as such there is no scope of any clarification that is required or warranted in facts and circumstances of the present investigation.
- e) None of the exporters from Indonesia and Thailand has cooperated in the present investigations and must, therefore, as per Anti

Dumping jurisprudence be declared non-cooperative and hence face the consequences of non-cooperation. Their non-cooperation itself evidences that the subject goods are being dumped in India by exporter of Indonesia. In the absence of complete data being submitted by the exporter either made available directly or through embassy of Indonesia, the Hon'ble Designated Authority would have no option under the present law except to declare them non-cooperative. With greatest respect, it is the submission of the domestic industry that in the aforementioned circumstances, the submissions made by the Government of Indonesia may not be taken into consideration.

- f) M/s. Citurgia Biochemicals Ltd., has expressed its full support for fixation of anti-dumping duty on citric acid originating in or exported from Indonesia and Thailand.
- g) We have studied the submissions from Indonesia and wish to state that adequate time was given prior to the preliminary imposition of anti dumping duty and adequate time has been given after the imposition of anti-dumping duty for parties to respond.

2.8 **REJOINDER OF IMPORTER**

M/s. Clariant (India) Ltd.,

- a) Importer has raised, whether the duty of US\$ 456.67/mt is based on full dumping margin or injury elimination level and also if the duty is based on full dumping margin then would not the injury elimination price would be higher.
- b) The petitioner has taken his own cost of production to establish the normal value which is over stated and it only reflects the inefficiency of the domestic industries in India.
- c) The origin for calculating the dumping on the basis of constructed cost has not been disclosed.
- d) Non-confidential submission of the petitioner is unverified.
- e) During the period 1999-2000 the petitioner has been operating at its full capacity and year 2000-2001 their both selling volume and selling price has increased which proves no injury.

2.9 **Price Undertaking offered by Indonesian Exporter**

M/s. P.T. BUDI ACID JAYA, Indonesia, who are the producer and exporter of Citric Acid have not responded in the prescribed

questionnaire in the present anti dumping case. However, after the public hearing 21st October 2002 they have proposed for a price undertaking offer.

2.10 **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

The Designated Authority proposes to consider all submissions made by interested parties on merits and in accordance with the Rules, consistent with the Articles of WTO Agreement and also the various provisions of the public hearing and disclosure of the non-confidential information as indicated in the anti dumping rules.

However, certain important issues raised by the petitioner/exporter and other interested parties have been examined by the Authority as under:

- a) Regarding the duty composition to the extent of dumping margin or injury elimination level, the Authority notes and proposes to recommend the anti dumping duty equal to the margin or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.
- b) The Authority notes, that notwithstanding the unsubstantiated argument raised by the importer/exporter regarding cost of production, the authority carried out the complete and detailed verification and examination of the books of accounts and records of the domestic industry.
- c) The level of non-injurious price is the information confidential to the domestic industry as the level is based on the costing information on all relevant factors concerning the production and the production process of the domestic industry.
- d) Regarding the issue raised by M/s. Clariant (India) Ltd., It is pointed that Column (1) of Para K(1) of preliminary finding dated 14th June 2002 denotes heading as Imports in MTs for the data in the same Column as in percentage terms. It is clarified that at the end of the said Table the figures are indexed. The abbreviation "MT" as mentioned in Column 1 is only to indicate that the indexation is being done to the physical quantities measured in Metric Tons and not the value.

Regarding Para K(b) of preliminary finding there is a typographical error in the last column as the last column of the previous Table seems to be erroneously mentioned in this Table as well. The actual figures in the last column, read as follows:-

| Year | % share |
|----------------------|---------|
| 1999-2000 | 49.82% |
| 2000-2001 | 53.67% |
| April-December, 2001 | 44.42% |
| Annualized | 44.42% |

2.11 In response to the disclosure, the following submissions have been made by domestic industry

M/s. Citurgia Biochemicals Limited

The domestic industry have reiterated their submissions made earlier and have mentioned that as there are no submissions to the contrary neither any objection on the issue of product under consideration, like article and standing of the Domestic Industry, they have requested to confirm the preliminary findings.

No responses were received either from the importer/user industry or exporter to the disclosure statement.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

The foregoing submissions made by the exporter, importer and the petitioner, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

3.1 PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Authority recalls and reiterates Para E 7 on the product under consideration of the preliminary findings dated 14.6.2002 as under:-

The product under consideration in the present petition is "Citric Acid" also known as Citric Acid Monohydrate. Citric Acid is a basic chemical normally classified under Customs sub-headings 2918.14 of the Custom Tariff Act 1975. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation. Citric Acid is used as preservative in food, soft drinks, confectionery, drugs, in textile dyeing and printing industry and has other industrial uses like in boiler cleaning etc.

The Authority has confirmed the preliminary finding on product under consideration, since no arguments were raised by the interested parties.

3.2 LIKE ARTICLE

The Authority recalls and reiterates Para F 8 on the Like Article of the preliminary findings dated 14.6.2002 as under:-

Rule 2(d) of the Anti Dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination. The Authority holds that Citric Acid being produced by the domestic industry and that being imported from the subject countries can be used interchangeably and thus the two are commercially and technically substitutable and therefore, are like articles within the meaning of the Rules.

There is no argument disputing that Citric Acid produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported product and is substitutable by the Citric Acid imported from the subject countries both commercially and technically. Citric Acid produced by the domestic industry has been treated as the Like Article to the product exported from Thailand and Indonesia, within the meaning of Rule 2(d),

In absence of any argument raised by the interested parties, the Authority has confirmed the preliminary finding on Like Articles.

3.3 STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

The Authority recalls Para G 9 on the Standing of the Domestic Industry of the preliminary findings dated 14.6.2002 as under:-

The petition has been filed by M/s Citurgia Biochemicals Ltd., on behalf of the domestic industry. Other producers of Citric Acid in India are M/s. Bharat Starch Industries Ltd. However, M/s. Bharat Starch Industries Ltd., was lying closed in the years 1999-2000 and 2000-01 and recommissioned their Citric Acid Plant only in the third week of December, 2001. Therefore, M/s Citurgia Biochemicals Ltd., have the standing to file the petition on behalf of domestic industry as per Anti Dumping Rules.

As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected

therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry." Further Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules states that Designated Authority shall not initiate any investigations pursuant to an application made under sub rule (1) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the Domestic Industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the Domestic Industry

The Authority notes that there is no opposition to the petition by any of the domestic producers and therefore confirms the standing of the domestic industry in view of no submissions and holds that the petitioner satisfies the condition as per Rule 5(3)(a) and (b) and represents domestic industry as per Rule 2(b).

3.4 PRICE UNDERTAKING

Rule 15 of Anti Dumping Rules relating to suspension or termination of investigation on price undertaking provides that the Designated Authority may suspend or terminate an investigation if the exporter of the article in question furnishes an undertaking in writing to the Designated Authority to revise the prices so that no exports of the said article are made to India at dumped prices, or in the case of imports from specified countries undertake to revise the prices so that injurious effect of dumping is eliminated and Designated Authority is satisfied that the injurious effect of dumping is eliminated.

M/s. P.T. BUDI ACID JAYA, INDONESIA

One of the exporters, M/s. P.T. BUDI ACID JAYA, INDONESIA had extended his willingness to offer price undertaking. The offer was examined in detail and the Designated Authority found that the undertaking offered by the exporter cannot be accepted as the exporter M/s. P.T. BUDI ACID JAYA, did not file the complete response to the Exporters questionnaire and thereby treated non cooperative by the Authority during the investigations.

3.5 **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN**

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

3.6 **Indonesia**

(a) **NORMAL VALUE:-**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Indonesia have provided the complete information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Citric Acid as per information available in the

petition. The Authority has adopted the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Citric Acid for all exporters from Indonesia has been taken at US\$ ***** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Indonesia has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority had adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics in the Preliminary Findings. The Authority has adopted the same for the final finding. Ocean freight, Marine insurance, inland freight and port charges to the extent of ****,****,**** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner has been considered. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

3.7 **Thailand**

(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Thailand has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Citric Acid as per information available in the petition. The Authority has adopted the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Citric Acid for all exporters from Japan has been taken at US\$ **** per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Thailand has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority had adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics in the Preliminary Findings. Ocean freight, Marine insurance, inland freight and port charges to the extent of ****,****,**** and **** \$/MT respectively based on the claim of the petitioner has been considered. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to **** \$/MT.

3.8 **DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE**

(a) The rules relating to comparison provides as follows: -

- (i) "While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time.
- (ii) Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability"
- (iii) The authority proposes to follow the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price, and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the anti dumping rules. Based on the Normal Values and Export Prices as indicated above the Authority assessed the Dumping Margins in case of all exporters/producers from the subject countries as given in the table below:-.

| Country-Wise Exporters/ Producers | Normal Value (\$/MT) | Export Price (\$/MT) | Dumping Margin (%) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Indonesia | **** | **** | 70.95% |
| Thailand | **** | **** | 55.08% |

D. 4.1 INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

4.2 **CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY**

It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority, therefore, proposes to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limit prescribed above. Cumulative assessment of effect of imports from Indonesia and Thailand are appropriate since the export prices from these countries were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market and displacing domestic producers.

- 4.3 As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure-II of the Anti Dumping Rules states:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

- 4.4 The Authority notes that the non-injurious price has been evaluated for the various domestic producers by appropriately considering the sales realisation from the related products. Also in order to eliminate inefficiencies, the Authority has normated and benchmarked the best practices on utilisation of raw materials, utilities etc..

- 4.5 As regards the injury which could happen on account of higher cost of production in India, the Authority notes that under the Indian Anti Dumping Rules it is the lesser duty rule which is applied.

- 4.6 The Authority has taken into account all indices regarding injury for the final determination. This would involve all relevant parameters viz. volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market and its subsequent effect on domestic producers, production, capacity utilization, profitability, net sales realization etc. While determining the Non Injurious Price for the like article for the domestic industry, the Authority has considered the optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and would also take into account the actual price of the raw materials during the Period of Investigation which go into the production of the product under consideration. While arriving at the injury margin, the Designated Authority takes into account optimum capacity utilization for arriving at a Non Injurious Price.

The Authority has also examined the various injury parameters as per the Annexure II of the Anti Dumping Rules and look into the various factors which could have caused injury to the domestic industry in order to establish the causality.

- 4.7 On the basis of the evidence available, the following parameters show existence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries:-

a) **Changes in Market Share held by the Indian producers.**

The Authority notes from the table below that the sales of the domestic industry has declined in absolute terms as well as in relation to the total demand in the country. Their market share has declined from 53.67 % in 2000-2001 to 44.42% in the period of investigation. The loss of market share becomes more significant as the total demand is showing an upward trend.

| Year | Domestic Sales | Total Demand | % share |
|---------------------|----------------|--------------|---------|
| 1999-2000 | 100.00 | 100 | 49.82% |
| 2000-2001 | 104.68 | 97 | 53.67% |
| April-December 2001 | 68.57 | 77 | 44.42% |
| Annualized | 91.42 | 103 | 44.42% |

Indexed

It is also observed that the imports from the subject countries in comparison to the total imports have increased drastically from 27.78% in 2000-2001 to 75.28%.

During the period of investigation. This increase is on account of the low prices of imports from these sources. Imports from the subject countries have also gone up in absolute terms leading to the loss of market share of the domestic industry.

| Year | Imports from Subject Countries (MT) | total Imports | % share |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1999-2000 | 100.00 | 100.00 | 9.68% |
| 2000-2001 | 257.40 | 89.72 | 27.78% |
| April-Dece 2001 | 662.39 | 85.19 | 75.28% |
| Annualized | 883.19 | 113.59 | 75.28% |

Indexed

Further, imports from the subject countries in comparison to the total demand in the country have also increased drastically from 4.86% in 1999-2000 to 12.87% in 2000-2001 and to 41.84% during the period of investigation.

| Year | Imports (MT) | Total Demand | % share |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| 1999-2000 | 4.86% | 100.00 | 4.86% |
| 2000-2001 | 12.87% | 97.18% | 12.87% |
| April-December 2001 | 41.84% | 76.91% | 41.84% |
| Annualized | 41.84% | 102.54% | 41.84% |

Indexed

b) **Output/Productivity & Capacity Utilization**

It is noticed that the domestic industry had been operating at fairly high levels of capacity utilization prior to the period of investigation. However, the capacity utilization of the petitioners declined from 98.59 % in 2000-2001 to 94.60 % in the period of investigation, a decline of about 4% over the period. It is also seen that there has been a drop in the production in the period of investigation over the preceding financial year.

| Year | Capacity (MT) | Production (MT) | Capacity Utilization (%) |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1999-2000 | 100 | 100.00 | 97.79% |
| 2000-2001 | 100 | 100.82 | 98.59% |
| April-December 2001 | 75 | 72.55 | 94.60% |
| Annualized | 100 | 96.73 | 94.60% |

c) **Sales Volume & Sales Value**

The Authority notes that there has been a significant decline in the sales volume of the domestic industry to the tune of 12.7% of the sales volume in the period of investigation as compared to the preceding year. It can be seen that there has been a decline in the selling price also in the period of investigation over the last year. While the decline in the selling price is marginal, it is important to note that the domestic industry has lost significant sales during the period. The Designated Authority is of the view that the domestic industry's attempt to maintain the same level of selling prices has to be seen in the context of the declining sales volume. Further, due to the sustained dumping from the subject countries, the domestic industry has been suffering losses on the sale of the subject goods in the period of investigation.

d) **Evidence of Lost Contracts**

The complainant domestic industry has argued that despite the efforts by them to hold on to the customers, the fact that 3670 MT of dumped imports arrived into India during POI is adequate evidence that it lost potential customers.

e) **Employment & Wages**

It has further been argued by the domestic industry that despite poor realization, they have made all attempts to sustain higher levels of production and capacity utilization and, therefore, there has been no impact on the employment. Further, injury to the domestic industry cannot be reflected in the employment figures as the Indian labour laws are rigid in this regard. There has been no impact on the wages for the same reasons as explained above.

f) **Profitability**

It has been argued by some of the importers/exporters that the Designated Authority need to examine the cost and the profitability of the domestic industry carefully and duly account for the inefficiency of the domestic industry. However, the Designated Authority notes that none of the opposing parties has given any concrete data or submissions to establish their claims. Notwithstanding the unsubstantiated arguments advanced by the exporters/importers, the Authority has carried out the complete and detailed verification of the books and records of the domestic industry. Based on this detailed examination, the Authority confirms its preliminary findings in this regard. As indicated in the preliminary findings, the domestic industry has suffered

serious injury in the form of direct losses per unit of sale. A comparison of the selling price and the cost of production per unit during the period of investigation clearly shows an increase in the loss per unit of sale. As indicated in the preliminary findings, it is apparent that it is the price factor alone which can be considered to have led to injury to the domestic industry resulting in losses.

| Year | Sales Value (Rs. In lakhs) | Cost of Sales (in lakhs) | Profit/Loss (in Lakhs) | Profitability |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1999-2000 | **** | **** | **** | **** |
| 2000-2001 | **** | **** | **** | **** |
| April-December 2001 | **** | **** | **** | **** |
| Annualized | **** | **** | **** | **** |

g) **Actual and Potential Negative Effect on Cash Flows & Growth**

As is clear from the above table, the domestic industry has suffered losses during the period of investigation which is obviously affecting their cash flows. Due to the losses in the industry and continued dumped imports, the domestic industry is also not in a position to make any new investments for expansion.

h) **Inventories**

The inventories have significantly increased from 687MT at the end of March 2001 to 1225MT as on 31.12.2001 and is, therefore, indicative of injury to the domestic industry.

i) **Magnitude of Margin of Dumping:**

As already indicated in the respective paras of these findings, the margins of dumping are as high as 71.95% and 55.08% for Indonesia and Thailand respectively.

j) **Price Undercutting**

It has been observed that dumping by the subject countries has had a significant impact on the net sales realization by the domestic industry for the subject goods. To hold on to its market share, the petitioner had to compete with low priced and dumped imports of subject goods from the subject countries. The landed values of the dumped imports also indicate that there is price under-cutting taking place.

k) **Price Underselling**

The Authority has also examined the claim of the domestic industry that the domestic industry is suffering on account of direct losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of injury. The Authority has worked out a fair selling price and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling.

l. **Return on investment & Ability to raise capital.**

The rate of return on the investment during the period of investigation for the product under consideration has been negative for the domestic industry as a result of which the domestic industry has not been able to raise fresh capital or plan new investment in this product.

E. **CAUSAL LINK**

5.1 In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

- a. The Authority observes that there is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. Decline in demand is not a factor causing injury to the domestic industry. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.
- b. The imports from subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.
- c. Dumped imports of subject goods from subject countries at dumped prices has resulted in substantial losses to the domestic industry.

5.2 The Authority has examined various economic factors and indices and has come to the following conclusions:

- 1) There has been a significant increase in the dumped imports of subject goods from subject country in absolute and relative terms.
- 2) The dumped imports had a significant effect on the domestic prices of subject goods which resulted in price undercutting
- 3) The dumped imports of subject goods have caused price suppression
- 4) The inventory of finished goods with the domestic industry has increased due to dumped imports.
- 5) The market share of the domestic industry has declined in the total demand.
- 6) The domestic industry has not been able to raise fresh capital or plan new investment.
- 7) The domestic industry is facing difficulty to raise the wages of its employees.

The above factors cumulatively have caused material injury to the domestic industry.

F. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

- 6.1 The purpose of anti dumping duties is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.
- 6.2 The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from Subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

G. FINAL FINDING

- 7.1 It would be seen, after considering the foregoing, that:
- (a) Citric Acid originating in or exported from Indonesia and Thailand have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping;
 - (b) The Indian industry has suffered material injury on account of price undercutting, price suppression and significant increase in the volume of dumped imports of subject goods from Indonesia and Thailand;
 - (c) The injury has been caused cumulatively to the domestic industry by the dumped imports from Indonesia and Thailand.
- 7.2 It is considered necessary to impose anti dumping duty, on all imports of Citric Acid originating in or exported from Indonesia and Thailand.
- 7.3 The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or injury, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed price of imports has been compared with the non injurious selling price of the petitioner company determined for the period of investigation.
- 7.4 Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty as indicated in Col. No. 3 below be imposed from the date of notification issued in this regard by the Central Government on Citric Acid originating in or exported from Indonesia and Thailand.

| Sl. No. | Exporters/ Producers | Amount of Anti Dumping Duty Recommended (US \$ per MT) |
|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Indonesia | All exporters/producers | 456.67 |
| Thailand | All exporters/producers | 374.36 |

- 7.5 The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act,

1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

- 7.6 Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 14.6.2002
- 7.7 An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority